नईदुनिया

दार्जिलिंग पहाड़ियों के लिए राजनीतिक समाधान पर मंथन

नईदुनिया ब्यूरो, सिलीगुड़ीः पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शनिवार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जुड़े मुद्दों के स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक के बाद भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने बताया कि केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे पर अंतिम समझौते के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के तहत बनाई गई यह समिति आज हुई चर्चा के आधार पर समझौते के प्रारूप को अंतिम रूप देगी। समिति की अध्यक्षता वार्ताकार पंकज कुमार सिंह करेंगे। बैठक का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए आगे की रणनीति तैयार करना था। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर बंगाल दौरे के अंतिम दिन दार्जिलिंग की तलहटी स्थित सुकना क्षेत्र के एक होटल में आयोजित की गई।

इससे पहले अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को इस मामले में सरकार का आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किया था।

आरक्षण और यूजीसी के विरोध में जंतर-मंतर पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी

सामान्य वर्ग के प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण और शिक्षा संबंधी नियमों में बदलाव की मांग उठाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को जाति आधारित आरक्षण और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी नियमों को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सामान्य वर्ग से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। उनका कहना है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर देने की मांग भी रखी। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, आर्थिक आधार पर आरक्षण और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी संबंधी नियमों में बदलाव शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन मुद्दों को लेकर सरकार और संबंधित संस्थाओं से कार्रवाई की मांग की। जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के कारण प्रदर्शन स्थल पर गतिविधियां बढ़ गईं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और संबंधित नीतियों में बदलाव की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उचित प्रतिनिधित्व मिले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी नियमों को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इन नियमों से जुड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान आरक्षण और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। जंतर-मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन जाति आधारित आरक्षण, आर्थिक आधार पर अवसर और उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव की मांगों पर केंद्रित रहा।

गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स बिर्केट दूसरे दौर की अनौपचारिक वोटिंग में सबसे आगे

80 साल बाद महिला महासचिव बनने की संभावना, यूएन की रेस में पांच महिलाएँ

न्यूयॉर्क,एजेंसीः संयुक्त राष्ट्र के 80 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला महासचिव बन सकती है। वर्तमान में महासचिव पद की दौड़ में आठ उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें पांच महिलाएं हैं। शुक्रवार को हुई दूसरे दौर की अनौपचारिक वोटिंग में गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स बिर्केट सबसे आगे रहीं, जबकि कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिन्सपैन दूसरे स्थान पर रहीं।

संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा महासचिव एंतोनियो गुटेरेस का दूसरा पांच वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नए महासचिव के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव सीधे जनता या सभी देशों की वोटिंग से नहीं होता। पहले सुरक्षा परिषद उम्मीदवारों के नामों पर विचार करती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो का अधिकार है।

किसी उम्मीदवार को सुरक्षा परिषद में आगे बढ़ने के लिए कम से कम नौ देशों का समर्थन चाहिए। हालांकि, स्थायी सदस्यों में से किसी एक का विरोध भी उम्मीदवार की राह रोक सकता है। सहमति बनने के बाद सुरक्षा परिषद उम्मीदवार के नाम की सिफारिश संयुक्त राष्ट्र महासभा को करती है, जहां 193 सदस्य देशों की मंजूरी के बाद नियुक्ति होती है। अनौपचारिक वोटिंग में सदस्य देश उम्मीदवारों के लिए समर्थन, विरोध या कोई राय नहीं का विकल्प चुनते हैं। 21 अगस्त की वोटिंग में कैरोलिन रोड्रिग्स बिर्केट को आठ देशों का समर्थन, तीन का विरोध और चार देशों ने कोई राय नहीं दी। इससे पहले 30 जुलाई की वोटिंग में रेबेका ग्रिन्सपैन को 10 देशों का समर्थन मिला था।

संयुक्त राष्ट्र में महासचिव पद के लिए अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की परंपरा रही है। वर्ष 1997 में महासभा ने भी चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय संतुलन और महिला-पुरुष समानता को ध्यान में रखने की बात कही थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि महासचिव किसी एक बड़ी शक्ति देश के प्रभाव में न दिखे। संयुक्त राष्ट्र में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की संख्या अधिक है, इसलिए इन क्षेत्रों के देशों की भी इच्छा रहती है कि महासचिव पद पर दुनिया के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व हो।

भारत से भी वर्ष 2006 में शशि थरूर महासचिव पद के उम्मीदवार रहे थे। उस समय भारत ने उनके संयुक्त राष्ट्र में लंबे अनुभव को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी रखी थी। थरूर कई दौर की अनौपचारिक वोटिंग में दक्षिण कोरिया के बान की-मून के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। अंतिम दौर में थरूर को 10 देशों का समर्थन मिला, लेकिन अमेरिका सहित तीन देशों के विरोध के कारण उनकी उम्मीदवारी आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद बान की-मून संयुक्त राष्ट्र महासचिव चुने गए।

बिना मुकदमे आतंकी निगरानी सूची में नाम

पीओके की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार को आतंकी बताया

बैंक खाते और यात्रा पर लग सकती हैं पाबंदियाँ

इस्लामाबाद, एजेंसीः पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हो रहे प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार और शोधकर्ता दानिश इरशाद का नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है। खास बात यह है कि सरकार की ओर से उनके खिलाफ किसी आतंकी गतिविधि का आरोप या अदालत का कोई फैसला सामने नहीं आया है। दानिश इरशाद पिछले करीब 10 वर्षों से पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान के राजनीतिक हालात और वहां की घटनाओं पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने पीओके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से जुड़ी खबरें प्रकाशित की थीं। इरशाद रावलपिंडी के रहने वाले हैं और उन्होंने वर्ष 2015 में इस्लामाबाद से पत्रकारिता शुरू की थी। वह लाहौर स्थित एक समाचार संस्थान से जुड़े हैं और जम्मू से प्रकाशित एक समाचार पत्र में स्तंभ भी लिखते हैं। उन्होंने 1947 के बाद जम्मू-कश्मीर के इतिहास पर एक किताब भी लिखी है। इरशाद के अनुसार, उन्हें न तो किसी मामले में अदालत में पेश किया गया और न ही किसी अपराध में दोषी ठहराया गया। उन्हें 18 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने पीओके के गृह विभाग के एक सूत्र से इसकी पुष्टि की। पाकिस्तान में फोर्थ शेड्यूल आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची मानी जाती है। इसमें शामिल लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इनमें विदेश यात्रा पर रोक, बैंक खातों और वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है। पत्रकार का नाम इस सूची में शामिल किए जाने को गंभीर कार्रवाई माना जा रहा है।

सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट, तीन इंजीनियरों की मौत

नईदुनिया ब्यूरो, रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात टरबाइन ब्लास्ट होने से तीन इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा फैक्ट्री में काम के दौरान हुआ। धमाके के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल कर्मियों ने नियंत्रित किया। मृतकों की पहचान रांची निवासी संजीव कुमार केसरी, बोकारो निवासी विनीत महतो और गढ़वा निवासी अभिषेक पांडेय के रूप में हुई है। घायल मजदूर तरुण रजवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूनिट इंचार्ज अनुराग त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि ओवरहीटिंग के कारण हादसा हुआ। तापमान नियंत्रित करने एसी लगाने की मांग की गई थी।

संसद में एक ही सत्र में विधेयक पारित होने की रफ्तार बढ़ी

मानसून सत्र में 12 में से 11 विधेयक पारित, सात पांच मिनट या उससे कम समय में हुए पास

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः संसद में विधेयक पेश करने और उन्हें पारित कराने की रफ्तार पिछले एक वर्ष में बढ़ी है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब तक पेश किए गए 64 विधेयकों में से 34 यानी 53 प्रतिशत विधेयक उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित हो गए, जिसमें उन्हें पेश किया गया था। यह आंकड़ा सत्रवार संसदीय आंकड़ों पर आधारित है। 16वीं लोकसभा में 189 में से 63 यानी 33 प्रतिशत विधेयक उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित हुए थे। 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया। इस दौरान पेश किए गए 190 विधेयकों में से 117 उसी सत्र में पारित हुए थे।

हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के लिए सरकार के मूल एजेंडे में पांच नए विधेयक पेश कर उन्हें पारित कराने तथा दो लंबित विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित कराने की योजना थी। हालांकि, संसद से पारित 11 विधेयकों में से छह मूल एजेंडे में शामिल नहीं थे। सरकार के एजेंडे में शामिल दो लंबित विधेयक भी पारित नहीं हो सके। इनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं।

18वीं लोकसभा की शुरुआत में एक ही सत्र में विधेयक पारित होने की रफ्तार अपेक्षाकृत कम थी। बजट सत्र में पेश 10 में से पांच विधेयक उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित हुए। वर्ष 2024 के बजट सत्र में पेश 11 में से एक भी विधेयक उसी सत्र में पारित नहीं हुआ था। इसके बाद शीतकालीन सत्र में पेश चार विधेयक भी लंबित रहे। 2025 से विधेयक पारित होने के इस पैटर्न में बदलाव आया। कम समय में विधेयक पारित होने को लेकर चिंता भी जताई गई है। इससे सांसदों को प्रस्तावित कानून की जांच करने और संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करने के लिए कम समय मिल सकता है। मानसून सत्र में नौ विधेयकों पर मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद ने चर्चा नहीं की। वहीं, 11 में से सात विधेयक पांच मिनट या उससे कम समय में पारित हो गए।

एयर होस्टेस से डीएसपी बनीं नेहा पच्चीसिया पर गिरफ्तारी की तलवार

जमीन सौदे से जुड़े मामले में एफआईआर के बाद बढ़ीं मुश्किलें

नईदुनिया ब्यूरो, कटनीः मध्यप्रदेश पुलिस की अधिकारी नेहा पच्चीसिया एक जमीन सौदे से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद चर्चा में हैं। कभी एयर होस्टेस के रूप में काम करने वाली नेहा ने बाद में पुलिस सेवा में प्रवेश किया और डीएसपी के पद तक पहुंचीं।

अब उनके खिलाफ दर्ज मामले के बाद गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। नेहा पच्चीसिया का शुरुआती करियर विमानन क्षेत्र से जुड़ा रहा। उन्होंने एयर होस्टेस के रूप में नौकरी की, इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पुलिस सेवा में चयनित हुईं और डीएसपी पद पर तैनात हुईं। उनके खिलाफ कटनी में जमीन सौदे से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि जमीन से संबंधित लेनदेन में अनियमितताएं हुईं। मामले में पुलिस जांच जारी है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा पच्चीसिया की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। नेहा पच्चीसिया इससे पहले भी अपने अलग-अलग करियर सफर को लेकर चर्चा में रही हैं। एयर होस्टेस से पुलिस अधिकारी बनने तक का उनका सफर लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। अब जमीन सौदे से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

सांसद कंगना रनौत ने खुद को बताया जेन-अल्फा

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अभिनेत्री का बयान चर्चा में, पहले जेन-जी को लेकर की थी टिप्पणी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए खुद को जेन-अल्फा बताया है। कंगना के इस पोस्ट के बाद उनके बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। कंगना इससे पहले जेन-जी यानी युवाओं की नई पीढ़ी को लेकर टिप्पणी कर चुकी हैं। उन्होंने जेन-जी को लेकर 'गटर जेनरेशन' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद यह बयान चर्चा में रहा था। अब उन्होंने खुद को जेन-अल्फा से जोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेन-अल्फा सामान्य तौर पर वर्ष 2010 के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी को कहा जाता है। वहीं जेन-जी को आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी के रूप में माना जाता है। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपने विचारों और टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनके राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन से जुड़े बयान समय-समय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। कंगना की ओर से जेन-अल्फा को लेकर किए गए पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका यह बयान युवाओं की पीढ़ियों और उनके विचारों को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया है।

नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी : विजय

1.28 लाख अंगूठियों के लिए 220 करोड़ रुपये का बजट, टेंडर प्रक्रिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत 1.28 लाख सोने की अंगूठियों के लिए 220 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (टीएनएमएससी) ने शुक्रवार देर रात जॉयलुक्कास और कल्याण ज्वेलर्स को अंगूठियों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश जारी किए हैं। ये अंगूठियां जून से सितंबर के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को दी जाएंगी। यह योजना 15 सितंबर को द्रविड़ आंदोलन के नेता सी. एन. अन्नादुरई की जयंती पर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास मजबूत करना है।

महँगाई *इथेनॉल उत्पादन से कीमत बढ़ने के दावे को खारिज, अक्टूबर में 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य...*

चीनी महँगी होने के पीछे जमाखोरी और कम उत्पादन जिम्मेदार: सरकार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा है कि इसके लिए इथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि कम उत्पादन, त्योहारी मांग और जमाखोरी के कारण बाजार में चीनी के दाम बढ़े हैं।

सरकार के अनुसार, चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक सीमा लागू करने और शुल्क मुक्त आयात जैसे कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल में मिलाने के लिए चीनी से इथेनॉल बनाने का हिस्सा वर्ष 2022-23 में 12 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर करीब 9 प्रतिशत रह गया है। वर्तमान में देश के कुल इथेनॉल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा अनाज, विशेषकर मक्के से तैयार किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि अतिरिक्त चीनी और गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में करने से चीनी मिलों को आर्थिक लाभ मिला है। इससे मिलों की भुगतान क्षमता बढ़ी और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो सका। 20 अगस्त 2026 तक इस सीजन का 97 प्रतिशत बकाया भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

मंत्रालय के अनुसार, पहले अतिरिक्त चीनी मिलों में जमा रहती थी, जिससे मिलों की पूंजी फंस जाती थी और किसानों को भुगतान में देरी होती थी। इथेनॉल नीति से इस समस्या को कम करने में मदद मिली है। सरकार ने बताया कि मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद उन्हें सब्सिडी की आवश्यकता भी कम हुई है।

वर्ष 2014 से 2021 के बीच सरकार ने मिलों को 14,600 करोड़ रुपये की सहायता दी थी, लेकिन वर्ष 2021-22 के बाद नई सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ी।

देश में खुदरा बाजार में पिछले एक महीने में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है। 20 जुलाई को चीनी का भाव 48.18 रुपये प्रति किलो था, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। सरकार ने बताया कि वैश्विक बाजार में भी चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है। 30 जून से 20 अगस्त के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव 474 डॉलर से बढ़कर 552 डॉलर प्रति टन हो गया।

वर्ष 2026-27 में वैश्विक स्तर पर करीब 33 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान है।

चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक सीमा लागू की है। महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा की खपत का भंडारण नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चीनी आयात को शुल्क मुक्त किया गया है और निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक रोक लगाई गई है।

सरकार ने मिलों को 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी है। इससे अक्टूबर में करीब 10 लाख टन चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 3 से 4 लाख टन उत्पादन होता है। सरकार का कहना है कि इससे त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।